Atal Bhujal Yojana- 'Taking a lead in Crop Diversification in Haryana'

Water conservation is a critical concern in agriculture, as it plays a significant role in ensuring food security and sustainable farming practices. In Haryana, Atal Bhujal Yojana is being implemented in 1656 over-exploited Gram Panchayats. The major concern of this depleting groundwater is paddy which is one of the high water guzzling crops. However, Atal Bhujal Yojana has proved to be a game changer in Haryana. IEC awareness activities along with capacity building of community has tried to mould the behaviour of farmers from flood irrigation to alternate crops, specifically vegetables like cauliflower, bitter gourd and bottle gourd. This has not even reduced the water consumption but also tried to meet the financial gains. Moreover, the subsidy benefit provided under Micro Irrigation systems has also attracted the farmers to grow the vegetables with drip system, thus reducing the water consumption to higher ends. It is worth noticing that Rice crop requires around 60-70 lakh litres of water per acre per crop cycle, however, vegetables grown with micro system consumes only 7.5 lakhs of water, thus reducing water usage upto 90%. It also enhances the yield upto 25-30%, depending upon the crop.

One such aware farmer is Shri Pankaj Singh s/o Gram Panchayat Subhri, Block Karnal who was inspired by Atal Bhujal Yojana and took a commendable step by cultivating vegetables on 8 acres. Shri Pankaj Singh said that he used to cultivate paddy crops traditionally in 8 acres of land but then he interacted with the team of Atal Bhujal Yojana in FY 2021-22, who visited their gram panchayat and gave detailed information about various demand and supply side interventions that can be undertaken through Atal Bhujal Yojana. With the help of the Atal Bhujal Yojana team, he applied for drip irrigation system in 8 acres. Thereafter, he started cultivated vegetables with drip system and started earning from alternate crop. He added that 'if every farmer cultivates alternate crops with different techniques, then they can earn more profit'. Influenced by Shri Pankaj, the farmers of the surrounding villages under Atal Bhujal Yojana started visiting their fields and applied for Micro Irrigation systems for vegetable cultivation.

कृषि में जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरियाणा में 1656 अतिदोहित ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना लागू की जा रही है। इस घटते भूजल की प्रमुख चिंता धान है जो पानी की अधिक खपत करने वाली फसलों में से एक है। हालांकि, अटल भूजल योजना हरियाणा में गेम चेंजर साबित हुई है। समुदाय के क्षमता निर्माण के साथ-साथ आईईसी जागरूकता गतिविधियों ने किसानों के व्यवहार को बाढ़ सिंचाई से वैकल्पिक फसलों, विशेष रूप से फूलगोभी, करेला और लौकी जैसी सब्जियों में ढालने की कोशिश की है। इससे न केवल पानी की खपत कम हुई है, बल्कि वित्तीय लाभ को पूरा करने की भी कोशिश की गई है। इसके अलावा, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के तहत प्रदान किए गए सब्सिडी लाभ ने भी किसानों को ड्रिप प्रणाली के साथ सब्जियां उगाने के लिए आकर्षित किया है, इस प्रकार पानी की खपत को कम किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि चावल की फसल को लगभग 60-70 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है।

ऐसे ही एक जागरूक किसान श्री पंकज सिंह पुत्र ग्राम पंचायत सुभरी, ब्लॉक करनाल हैं, जिन्होंने अटल भूजल योजना से प्रेरित होकर 8 एकड़ में सब्जियों की खेती कर के एक सराहनीय कदम उठाया। श्री पंकज सिंह ने कहा कि वे 8 एकड़ भूमि में पारंपरिक रूप से धान की खेती करते थे, लेकिन फिर उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 में अटल भूजल योजना की टीम के साथ बातचीत की, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत का दौरा किया और अटल भूजल योजना के माध्यम से किए जा सकने वाले विभिन्न मांग और आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेपों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अटल भूजल योजना की टीम की मदद से उन्होंने 8 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए आवेदन किया। इसके बाद, उन्होंने ड्रिप प्रणाली के साथ सब्जियों की खेती शुरू की और वैकल्पिक फसल से कमाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हर किसान अलग-अलग तकनीक के साथ वैकल्पिक फसलों की खेती करता है, तो वे अधिक लाभ कमा सकते हैं। श्री पंकज से प्रभावित होकर अटल भूजल योजना के तहत आसपास के गांवों के किसानों ने अपने खेतों में जाकर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए आवेदन किया।